नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

3 136 परिवारों को मिला घर और जमीन : योगी

4 पाप का घड़ा फूटते देर नहीं अब खरात की खैर नहीं

9 रिफिल बुकिंग का अलग प्रावधान नहीं

11 सिनर की मियामी क्वार्टरफाइनल में दमदार एंट्री

10 साल में 100 एयरपोर्ट

28840 करोड़ संशोधित 'उड़ान' योजना के लिए मंजूर | **200** आधुनिक हेलीपोर्ट का किया जाएगा निर्माण | **1.62** करोड़ लोगों ने रियायती दरों पर की यात्रा

- पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक
- केंद्र 12,159 करोड़ की देगी बजटीय सहायता

नई दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता) केंद्र सरकार ने बुधवार को 28,840 करोड़ रुपये की लागत से 10 साल की संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत देश में 100 नये हवाई अड्डों और 200 आधुनिक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई.

उल्लेखनीय है कि छोटे तथा मझौले शहरों को देश के हवाई नेटवर्क में शामिल करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) उड़ान की शुरुआत साल 2016 में की गई थी और पहली फ्लाईट दिल्ली से शिमला के बीच अप्रैल 2017 में शुरू हुई थी. इसके तहत 95 नये हवाई अड्डों की शुरुआत की गई है, जिनमें ज्यादातर पुरानी हवाई पट्टियों और उपेक्षित हवाई अड्डों को विकसित करके बनाए गए हैं.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि उड़ान योजना में 1.62 करोड़ लोगों ने रियायती दरों पर यात्रा की है. वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 के लिए मंजूरी नई योजना में चार करोड़ यात्रियों का लक्ष्य रखा गया है.

उन्होंने बताया कि आठ साल में 100 नए हवाई अड्डों का विकास चैलेंज मोड में किया जाएगा. राज्य बताएंगे कि किन शहरों को शामिल करना चाहते हैं, उसके लिए जमीन, वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरी आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी. केंद्र सरकार हवाई अड्डों के विकास के लिए कुल 12,159 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता देगी. एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि सभी 100 हवाई अड्डे पुरानी हवाई पट्टियों को विकसित करके ही बनाए जाएंगे. इससे 120 नए शहर उड़ान में शामिल होंगे.

आईवीएफआरटी का क्या है उद्देश्य

आईवीएफआरटी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में इमिग्रेशन, वीजा जारी करने और विदेशियों के पंजीकरण से जुड़े कामों को आपस में जोड़ना और उन्हें बेहतर बनाना है. इसका मुख्य लक्ष्य एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा वितरण ढांचे के तहत इमिग्रेशन और वीजा सेवाओं का आधुनिकीकरण करना है. इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और वैध यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

ईरान-इजराइल जंग के बीच सर्वदलीय बैठक, विपक्ष सरकार के साथ

नई दिल्ली, 25 मार्च. ईरान-इजराइल जंग के बीच सरकार ने बुधवार को सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की. बैठक की अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने की. बैठक में मिडिल ईस्ट पर के हालातों और देश में गैस-तेल की उपलब्धता सरकार ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सरकार के साथ है. वहीं बैठक से बाहर निकले कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि विपक्ष की मुख्य मांग है कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर लोकसभा और राज्यसभा में विस्तृत चर्चा कराई जाए. बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के मिडिल ईस्ट के हालतों पर ब्रीफिंग दी. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और विदेश सचिव विक्रम मिसरी शामिल रहे.

ये नहीं हुए शामिल

बैठक से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बैठक में शामिल ना होने का फैसला लिया है. वहीं, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी बैठक में शामिल नहीं हुए.

सीएम ने सादगी से मनाया जन्मदिन

सागर, 25 मार्च. सीएम डॉ. मोहन यादव बुधवार को सागर जिले के गांव मोहली पहुंचे, उन्होंने पहले गाय को चारा खिलाया और फिर खाट पर बैठकर भोजन किया. सीएम के साथ विधायक गोपाल भार्गव भी मौजूद थे.

ईरान से जंग खत्म करा सकता है भारत

- इजरायली राजदूत रुविन अजार बोले
- अमेरिका ने घोषणा के दूसरे दिन भी नहीं किया हमला

तेल अवीव, 25 मार्च. यूएस-इजराइल और ईरान की जंग 26 दिनों से जारी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पांच दिनों तक ईरान के परमाणु प्लांट पर हमले नहीं करने की घोषणा की थी. बुधवार को दूसरे दिन भी अमेरिका की ओर से कोई हमला नहीं किया गया.

ईरान जंग को खत्म कराने में भारत की भूमिका काफी अहम हो सकती है. नई दिल्ली में इजरायल के राजदूत रुविन अजार ने कहा कि वेस्ट एशिया में भारत का बड़ा स्टेक है. दूसरी तरफ, इस मामले में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की बतौर मध्यस्थ की भूमिका पर भी रुविन ने बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान, तुर्की समेत अन्य देशों की क्या भूमिका होगी, इसका फैसला अमेरिका ही करेगा. साथ ही रुविन अजार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह हफ्ता ईरान के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है.

अमेरिका ने दिया 15 सूत्रीय प्रस्ताव

वाशिंगटन. अमेरिका ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से ईरान को 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक पहल हो सकती है. हालांकि ईरान ने किसी भी प्रकार की बातचीत होने से स्पष्ट इनकार किया है. अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान में मध्यस्थों के माध्यम से भेजा गया था.

एक नजर में

5वीं के 95 और 8वीं के 93 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास

भोपाल. मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने बुधवार को कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी किया. स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने वल्लभ भवन में एक कार्यक्रम के दौरान बटन दबाकर रिजल्ट घोषित किया. इस साल 5वीं के 95.14 प्रतिशत और 8वीं के 93.83 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं. दोनों कक्षाओं में छात्रों की तुलना में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया है. 8वीं के पासिंग स्टूडेंट्स के परसेंटेज में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का नरसिंहपुर जिला नंबर वन पर है. इंदौर का 9वां स्थान है और भोपाल टॉप टेन से बाहर है.

पब्लिक इवेंट्स में वंदेमातरम अनिवार्य नहीं

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और सरकारी संस्थानों में रोजाना 'वंदे मातरम' गाने को अनिवार्य बनाने वाले केंद्र सरकार के सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने याचिका को प्री-मैच्योर करार देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार की निर्देशिका या सलाह के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो तो सुनवाई का कोई अर्थ होगा, इसलिए सुनवाई की जरूरत नहीं है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि सरकार की एडवाइजरी या निर्देशिका के आधार पर अगर किसी के साथ कोई भेदभाव या जबरदस्ती होती है, तभी अदालत दखल देगी.

अदालत ने मेटा पर 3100 करोड़ का लगाया जुर्माना

वॉशिंगटन. अमेरिका ने टेक दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक मेटा को मुश्किल में डाल दिया है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप जैसे प्लेटफॉर्म चलाने वाली इस कंपनी पर जुर्माना लगाया है और वजह है बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला. न्यू मेक्सिको की एक जूरी ने मेटा पर करीब 375 मिलियन डॉलर (लगभग 3100 करोड़ रुपये) का जुर्माना ठोका है. करीब सात हफ्तों तक चली लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया. सरकारी वकीलों ने अदालत में कहा कि मेटा को पहले से पता था कि उसके प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने इन खतरों को खुलकर सामने नहीं आने दिया.

जाति मुक्त समाज बनाना था हम तो बांटने लगे : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 25 मार्च. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ा. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि देश में हमें एक जाति मुक्त समाज बनाना था, लेकिन हम लगातार बंटते जा रहे हैं.

इसके साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने 2027 की जनगणना में 'विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों' की अलग से गणना करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह एक नीतिगत निर्णय है और यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने की छूट दी है. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, भारत एक बहुत ही अनूठा देश है.

बंगाल में बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी

कोलकाता, 25 मार्च. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है. सूची में 19 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं. बीजेपी ने कूचबिहार दक्षिण से रथीन्द्र नाथ बोस, राजगंज (एससी) से दिनेश सरकार (हराधन सरकार), इस्लामपुर से चित्रजीत राय, हेमताबाद (एससी) से हरिपद बर्मन, इंग्लिश बाजार से अमलन भादुरी, शांतिपुर से स्वपन दास, पानी हाटी से रत्ना देबनाथ को टिकट दिया है.

जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना खुला

आरबीआई लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने

पुरी, 25 मार्च. ओडिशा में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की बहुप्रतीक्षित लिस्टिंग की प्रक्रिया 48 सालों बाद बुधवार को शुरू हो गई. इस प्रक्रिया में मंदिर के कर्मचारी, सरकारी बैंक के अधिकारी, रत्न विशेषज्ञ और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रतिनिधि भी शामिल हैं.

श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के अनुसार, अधिकृतकर्मियों ने पारंपरिक धोती और गमछा पहनकर सुबह करीब 11.30 बजे मंदिर में प्रवेश किया.

पहले कब हुई थी गिनती : इससे पहले 13 मई से 23 जुलाई, 1978 के बीच गणना हुई थी. इसमें 128.38 किलोग्राम के 454 स्वर्ण मिश्रित आभूषण, 221.53 किलोग्राम वजन के 293 चांदी मिश्रित आभूषण और कई बहुमूल्य रत्नों का विवरण दर्ज किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि 1978 की प्रक्रिया 72 दिन चली थी, लेकिन इस बार आधुनिक तकनीक के उपयोग से इसे कम समय में पूरा किया जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री शाह बोले | गुजरात, उत्तराखंड के बाद यह विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य

सभी नागरिकों के लिए समान कानून प्राथमिकता

नई दिल्ली, 25 मार्च (वार्ता) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है कि देश तुष्टिकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले.

गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर गृह मंत्री शाह ने यह बात कही. बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं.

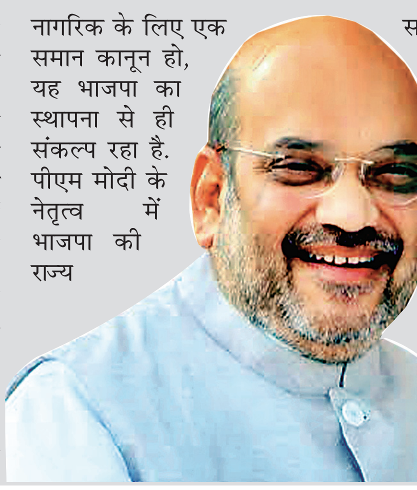

मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है. इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस विधेयक को समर्थन देने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूं.

उल्लेखनीय है कि गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित किया, जिससे राज्य में सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए समान कानून बन गया है. गुजरात, उत्तराखंड के बाद यह विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है.